Non-implementation of Sports Quota for recruitment

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी खेल को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प हैं।

महोदय, विगत कई वर्षों के उपरांत, क्रीड़ा कोटे के अधीन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य विशेष क्रीड़ा के उदीयमान खिलाड़ियों के कौशल पर रेलवे नियुक्ति प्रदान करता है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक रेलवे के लिए समय-समय पर रिक्तियों की उपलब्धता जारी की जाती है, जिस पर प्रत्येक रेलवे खेल की कुशलता बढ़ाने के लिए मुख्यालय व मंडलों में सीटों का बंटवारा किया जाता है। उक्त संबंध में तृत्तीय श्रेणी का ट्रायल मुख्यालय तथा चतुर्थ श्रेणी का ट्रायल मंडलों द्वारा किया जाता रहा है, जिससे खिलाड़ियों को अवसर मिलते हुए, मंडलों की विभिन्न टीमों का संतुलन बना रहता है, परंतु मुख्यालय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रायल आरआरसीबी मुख्यालय से करने पर उचित चयन हो पाता है, जिसका असर मंडल की टीमों पर पड़ता है। अतः अनुरोध है कि क्रीड़ा कोटे की रिक्तियों का बंटवारा करते हुए, मंडलों में ट्रायल कराया जाए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के खिलाड़ियों को अवसर प्राप्त हो सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shrimati Seema Dwivedi: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

श्री मुजीबुल्ला खान - Request to incorporate the recommendations for the National Tourism Policy. उपस्थित नहीं हैं। डा. के. लक्ष्मण। Concern over mismanagement at the Sabrimala Temple, Kerala.

Mismanagement at the Sabrimala Temple, Kerala

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I will speak in Telugu on this subject.

*"Hon'ble Deputy Chairman Sir, devotees of Ayyappa Swamy, who are spread across the world, in the months of December and January, wear the Ayyappa mala, observe tough Deeksha for forty days and visit the Ayyappa Swamy temple in Sabarimala. When lakhs of devotees from Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala wear Ayyappa mala and visit the temple with utmost fervour, the State Government is behaving in an indifferent manner by not providing even the basic facilities. Because of this, the suffering of the devotees is indescribable. The

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

Kerala Government is not concerned about the suffering of the devotees even when the devotees have to wait for more than twenty hours for darshan and when many lives are being lost in the stampede. The Kerala Government is behaving in a revengeful manner towards the devotees of Sri Ayyappa Swamy. The Government is ordering lathi charge on the devotees who observe the deeksa with utmost fervor. There is nothing worse than this. Padmasree, a twelve-year old girl from Tamil Nadu, lost her life during Ayyappa darshan. Fifteen-year-old Rajesh Pillai also died. Ayyappa devotees are suffering a lot because basic amenities like water, food, sanitation and transportation are not provided to them. People are watching this anti-Hindu approach by the Kerala Government. On 14th January 2011, on the occasion of Makara Jyoti, 106 people lost their lives in the stampede. The Kerala Government is in deep slumber even after the directions by the hon. Kerala High Court to provide facilities and the matter being discussed in the Parliament too. The discrimination shown by the Kerala Government towards the devotees is like supporting the forces which want to destroy the Sanatana Dharma. The Kerala Government is showing negligence towards the Hindu temples. Mughals, Turkish, Mir Qasim, Aurangzeb, Muhammad Ghazni and many others tried to destroy the Sanatana Dharma. They waged many wars and attacks to destroy Sanatana Dharma. But, Indian Sanatana Dharma stood strong against these attacks thus spreading its greatness and strength across the world. Those who wanted to end the Sanatana Dharma ended themselves but the Sanatana Dharma is eternal. Spiritual feeling and spiritual strength is growing in the Hindus. At least now, I request the people to understand the Congress and Communists who are wearing the mask of secularism but are anti-Hindu in approach deep down in their veins. I request the Central Government to deploy Central Forces, CRPF, NDRF and additional forces and also provide basic facilities to the devotees and come to their rescue. Thank you, Sir."

श्री उपसभापतिः धन्यवाद डा. के. लक्ष्मण।

The following Members associated themselves with the matter raised by Dr. K. Laxman: Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Dr. Sonal Mansingh (Nomianted), Shri Sadanand Shet Tanawde (Goa), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri R. Dharmar (Tamil Nadu), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shri Lahar Singh Siroya (Karnataka), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri G.V.L. Narasimha Rao (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Ayodhya Rami Reddy Alla (Andhra Pradesh), Shri

Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh).

Shri Sujeet Kumar - 'Demand for exempting GST for Handloom Sector'.

Demand for exempting GST for Handloom Sector

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हैंडलूम उत्पाद पर जीएसटी हटाने के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि खादी या खादी के उत्पाद, चरखा या जो हैंडलूम वीविंग मशीनरी है, उन पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो धागा, कॉटन फाइबर, यार्न है, उनमें 5 प्रतिशत जीएसटी है। इनमें पहले जीएसटी लागू नहीं था। सर, जो हैंडलूम का फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। इसके अलावा जो हैंडलूम गारमेंट्स हैं, उन पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। हमारे जो बुणाकार भाई हैं, जो यह काम करते हैं, उनको हैंडलूम उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। इससे कन्ज़्यूमर्स उस उत्पाद को नहीं खरीदते हैं, जिससे उनकी आजीविका पर फर्क आता है। इससे हमारे देश में हैंडलूम की जो बहुत बड़ी परंपरा है, उस पर प्रभाव पड़ता है।

महोदय, हमारे देश में करीबन 44 लाख वर्कर्स हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 14 प्रतिशत है। सिर्फ ओडिशा में ही करीबन साढ़े तीन लाख हैंडलूम बुणाकार हैं। झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगढ़, सोनपुर और बलांगीर ऐसे जिले हैं, जहां पर मैक्सिमम इकोनॉमी हैंडलूम सेक्टर्स से चलती है। इसके चलते इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीएसटी का जो फॉर्म फिल-अप, उसका जो प्रोसीज़र है, यह बहुत कम्बरसम है। हम एक बुणाकार से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह खुद जाकर जीएसटी का फॉर्म भरे और जीएसटी की फाइलिंग करे। इसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स आदि के पास जाना पड़ता है और उससे उसका खर्चा बढ़ता है।

महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ओडिशा सरकार हमारे बुणाकार भाइयों को मदद करने के लिए काफी स्कीम्स लाई है। उनमें से एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत उनको एक लाख रुपये तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, उसको 'बलिया' (BALIA) स्कीम कहते हैं - Bunakar Assistance for Livelihood and Income Augmentation, इस विषय पर कई बार ओडिशा सरकार भारत सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। प्रशांत नन्दा जी ने यह विषय 19 दिसम्बर, 2018 में अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत संसद में उठाया था और 11 जुलाई, 2019 को भी यह विषय एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था।

महोदय, मैं मानता हूं कि जीएसटी तभी भरना पड़ता है, जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो और यह भी सही है कि बहुत सारे बुणाकार हैं, जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है। फिर भी अगर हम लोग उनकी लाइवलिहुड को बढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड मार्किट में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इससे उनका टर्नओवर जरूर बढ़ेगा। यह 20 लाख से नीचे वाला जो exemption है, इससे भी उनको आगे चलकर फायदा नहीं होगा। दूसरा, यह भी सच है कि जीएसटी का जो रेट है, इसको जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें स्टेट भी 50 प्रतिशत भागीदार होती है। हमारे यहां पर डा. कराड़ हैं, वे बहुत ही कॉम्पिटेंट एमओएस, फाइनेंस